

राजस्थान सरकार
राजरथ (युप-6) विभाग

क्रमांक पा० १(४)राज-६/२००१/पार्ट/०२

जयपुर, दिनांक २४.०५.१६

समरत जिला कलक्टर,
राजस्थान।

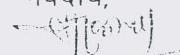
—परिपत्रः—

विषयः— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु निःशुल्क राजकीय भूमि आवंटन के संबंध में।

मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 70/2016 दिनांक 14.04.2016 के कम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राजकीय भूमि दिनांक 21.01.1976 से निःशुल्क आवंटित करने एवं आदिनांक बकाया राशि माफ की स्वीकृति दिये जाने तथा भविष्य में राजकीय भूमि निर्धारित शर्तों पर निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त निर्णय की क्रियान्विति के अनुसरण में विभाग के परिपत्र क्रमांक पा० १(४)राज-६/२००१/५ दिनांक 23.06.2004 को आंशिक रूप से अधिष्ठित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राजकीय भूमि निम्नांकित शर्तों पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण (Widening) हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखण (Allignment) में आ रही राजकीय भूमि का निःशुल्क आवंटन इस शर्त के साथ किया जावेगा कि राज्य की विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं के लिए जब भी आवश्यकता होगी, उपयोगिता गलियारे (utility corridor) का अधिकार राज्य सरकार का पूर्ण सङ्क मार्ग पर निःशुल्क रहेगा।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवंटित की जाने वाली भूमि के संबंध में समरत दायित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के होगे।
- यदि कोई सार्वजनिक सम्पत्ति या राज्य सम्पत्ति सङ्क सीमा में स्थित है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा नियमानुसार मुआवजे का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवंटित की जाने वाली भूमि पर किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि का संचालन नहीं किया जायेगा। यदि कोई वाणिज्यिक गतिविधि आरम्भ की जायेगी तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भूमि का मूल्य डॉ०एल०री० दर पर अदा करने हेतु दायित्वाधीन रहेगा।

परिपत्र दिनांक 23.06.2004 भारतीय रेलवे को रेलवे लाईन डालने, रटेशनों के निर्माण तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि के संबंध में यथावत लागू रहेगा।

भवदीय,

(डॉ० कुंज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव